भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5022

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

अधिकरणों में रिक्तियाँ

5022. डॉ. थोल तिरुमावलवन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकरणों/अपीलीय अधिकरणों में रिक्तियों को भरा नहीं गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकरणों की संख्या कितनी है और उनमें कितनी रिक्तियां हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) रिक्तियों को न भरने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : अधिकरणों/अपील अधिकरणों में रिक्तियों को भरा जाना एक नियमित कवायद है । 9 मंत्रालयों/विभागों के 12 अधिकरणों के संबंध में प्राप्त की गई सूचना नीचे दी गई सारणी में उपाबंधों के रूप में रखी गई है :

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	अधिकरण/अपील अधिकरण का नाम	उपाबंध
1	विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	आय-कर अपील अधिकरण	**I**
2	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी)	**II**
3	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण	**III**

		(सीएटी)	
4	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजेटी)	**IV**
5	रेल मंत्रालय	रेल दावा अधिकरण	**V**
6	राजस्व विभाग	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी) और अपील अधिकरण (एसएएफईएमए)	**VI**
7	वित्तीय सेवाएं विभाग	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) और ऋण वसूली अपील अधिकरण (डीआरएटी)	**VII**
8	रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय	सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी)	**VIII**
9	दूरसंचार विभाग	दूरसंचार विभाग विवाद निपटारा और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी)	**IX**

****

<u>उपाबंध-1</u>

<u>विधि कार्य विभाग (आयकर अपील अधिकरण):</u>

(**क) से (ग)** : आईटीएटी की 63 न्यायपीठों से मिलकर बना है । देश भर के 30 स्टेशनों (जिसके अंतर्गत 02 सर्किट न्यायपीठें भी हैं) में विस्तृत 63 न्यायपीठों के लिए वर्तमान में एक (01) अध्यक्ष और दस (10) आंचलिक उपाध्यक्षों सहित 126 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं । रिक्तियों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है । हाल ही में, सरकार ने उक्त अधिकरण में लेखा/न्यायिक सदस्यों की 21 रिक्तियां भरी हैं । आज तक, स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	लेखा सदस्य	63	43*	20
2	न्यायिक सदस्य	63	47^	16
	कुल	126**	90	36

* 01 अध्यक्ष और 04 उपाध्यक्षों को सम्मिलित करते हुए,

^04 उपाध्यक्षों को शामिल करते हुए;

** अध्यक्ष का एक पद और दस उपाध्यक्ष सम्मिलित हैं ।

अध्यक्ष, आईटीएटी के पद को नियमित आधार पर भरने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है । उक्त पद नियमित अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति पर तारीख 05.09.2021 को रिक्त हो गया था ।

उपाबंध-2

कारपोरेट कार्य मंत्रालय **{**राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण(एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी)**}:**

(क) और (ख): एनसीटीएल और एनसीएलएटी के सदस्यों की रिक्ति की आज तक की स्थिति निम्नानुसार है:

अधिकरण का नाम	रिक्तियों की संख्या	तारीख से रिक्त पद	
एनसीएलटी	कुल-15 न्यायिक सदस्य - 9 तकनीकी सदस्य- 6	न्यायिक सदस्य 1. 02/10/2019 2. 23/10/2019 3. 01/01/2020 4. 11/09/2020 5. 20/01/2021 6. 02/06/2021 7. 10/06/2021 8. 01/07/2021 9. 01/09/2021	तकनीकी सदस्य 1. 04/03/2020 2. 10/03/2020 3. 05/05/2021 4. 23/06/2021 5. 26/06/2021 6. 01/10/2021
एनसीएलएटी	कुल- 5 न्यायिक सदस्य - 3 तकनीकी सदस्य- 2	न्यायिक सदस्य 1. 19/04/2021 2. 11/09/2021 3. 23/01/2022	तकनीकी सदस्य 1. 01/07/2021 2. 21/02/2022

(ग) : रिक्तियों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और रिक्त पद समय समय पर भरे जाते हैं । एनसीएलटी और एनसीएलएटी में वर्तमान रिक्तियों के संबंध में, पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो संबंधित चयन समिति और खोज-सह-चयन समिति के विचाराधीन है ।

<u>उपाबंध-3</u>

<u>कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण):</u>

(क) और (ख) : देश भर में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) की 19 नियमित न्यायपीठें हैं । अध्यक्ष के 01 पद सहित सदस्यों की कुल स्वीकृत संख्या 70 है । आज तक स्वीकृत 70पदों में से 33 पद भरे हुए हैं और 37 पद रिक्त हैं । आज तक, सीएटी में रिक्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	न्यायिक सदस्य	प्रशासनिक सदस्य	कुल
1	सदस्यों की स्वीकृत संख्या	34+01*	35	70
2	कुल रिक्तियां	18*	19	37

*अध्यक्ष का 01 रिक्त पद: अध्यक्ष का पद न्यायिक स्ट्रीम में दर्शाया गया है, क्योंकि पिछला पदधारी न्यायिक स्ट्रीम से था । नियम, 2021 के अनुसार यह या तो न्यायिक या प्रशासनिक सदस्य हो सकता है ।

(ग) : इन पदों के रिक्त होने का कारण यह है कि वर्ष 2019, 2020 और 2021 की रिक्तियों को अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों की सेवा शर्तों को शासित करने वाले नियमों के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में जारी मुकदमों के कारण नहीं भरा जा सका था । तथापि, अब अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के जारी होने के पश्चात् सीएटी के सदस्यों का चयन करने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के एक पीठासीन अधिकारी को उसके अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हुए और अन्य सदस्यों वाली उच्च-स्तरीय खोज-सह-चयन समिति के गठन के साथ प्रारंभ हो चुकी है

<u>उपाबंध-4</u>

<u>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) :</u>

(क) से (ग) : वर्तमान में, अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं है । एनजीटी में पांच (05) न्यायिक सदस्यों के पद रिक्त हैं । तथापि, डीओपीटी ने अपने पत्र संख्या 9/5/2022-ईओ(एसएम.2), तारीख 10.03.2022 द्वारा न्यायिक सदस्यों के पदों पर पांच (05) अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए एसीसी के अनुमोदन के लिए संसूचित किया था । मंत्रालय ने तारीख 21.03.2022 को सभी पांच अभ्यर्थियों को प्रस्ताव पत्र जारी कर दिए थे । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में विशेषज्ञ सदस्यों के चार (04) पद रिक्त हैं । सरकार, विशेषज्ञों सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही कर रही है । एनजीटी में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की रिक्तियां माननीय सदस्यों की पदावधि पूरी होने और माननीय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण है । मंत्रालय, एनजीटी में उदभूत होने वाले न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों के संभाव्य रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक अग्रिम कार्रवाई करने का प्रयास करती है ।

उपाबंध-5

रेल मंत्रालय (रेल दावा अधिकरण):

क. जी हां

ख. रेल दावा अधिकरण (आरसीटी) की न्यायापीठों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य (न्यायिक) और सदस्य (तकनीकी) के रिक्त पदों के ब्यौरे:-

उपाध्यक्ष की स्थिति:

क्र.सं.	न्यायपीठ का नाम	पद का नाम	वह तारीख जब से पद रिक्त है
1.	इलाहाबाद	उपाध्यक्ष (तकनीकी)	13.09.2019
2.	कोलकाता	उपाध्यक्ष (तकनीकी)	22.08.2021
3.	मुम्बई	उपाध्यक्ष (न्यायिक)	28.04.2020
4.	सिकंदराबाद	उपाध्यक्ष (न्यायिक)	05.06.2020

सदस्य (न्यायिक) की स्थिति

क्र.सं.	न्यायपीठ का नाम	पद का नाम	वह तारीख जब से पद रिक्त है
1.	दिल्ली	सदस्य (न्यायिक)	16.06.2020
2.	लखनऊ	सदस्य (न्यायिक)	04.05.2020
3.	गोरखपुर	सदस्य (न्यायिक)	01.05.2019
4.	चंडीगढ़*	सदस्य (न्यायिक)	01.10.2021
5.	कोलकाता	सदस्य (न्यायिक)	10.06.2019
6.	भुवनेश्वर	सदस्य (न्यायिक)	27.10.2015
7.	गुवाहाटी**	सदस्य (न्यायिक)	01.01.2022
8.	गुवाहाटी**	सदस्य (न्यायिक)	31.03.2017
9.	रांची	सदस्य (न्यायिक)	23.01.2018
10.	मुम्बई	सदस्य (न्यायिक)	23.08.2017
11.	भोपाल***	सदस्य (न्यायिक)	26.06.2021
12.	जयपुर****	सदस्य (न्यायिक)	18.09.2021
13.	नागपुर	सदस्य (न्यायिक)	07.04.2018
14.	बैंगलौर	सदस्य (न्यायिक)	01.06.2019
15.	चैन्नई	सदस्य (न्यायिक)	29.08.2018
16.	एर्नाकुलम	सदस्य (न्यायिक)	12.07.2019

सदस्य (तकनीकी) की स्थिति

क्र.सं.	न्यायपीठ का नाम	पद का नाम	वह तारीख जब से पद रिक्त है
1.	रांची	सदस्य (तकनीकी)	18.09.2021
2.	अहमदाबाद	सदस्य (तकनीकी)	16.12.2020
3.	नागपुर	सदस्य (तकनीकी)	19.02.2021
4.	बैंगलौर	सदस्य (तकनीकी)	10.09.2021
5.	चैन्नई	सदस्य (तकनीकी)	09.09.2021
6.	एर्नाकुलम	सदस्य (तकनीकी)	11.12.2014
7.	अमरावती	सदस्य (तकनीकी)	07.09.2020

पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पद
अध्यक्ष	1	1	0
उपाध्यक्ष (न्यायिक)	2	0	2
उपाध्यक्ष (तकनीकी)	2	0	2
सदस्य (न्यायिक)	20	4	16
सदस्य (तकनीकी)	21	14	7
कुल	46	19	27

टिप्पण:-

*आरसीटी, चंडीगढ़ में तारीख 20.04.2020 से पद रिक्त था । श्री लाभ सिंह, सदस्य (न्यायिक) ने तारीख 27.09.2021 को आरसीटी, चंडीगढ़ में पद ग्रहण किया था और उसके पश्चात् उन्हें आरसीटी, गुवाहाटी में स्थानांतरित कर दिया गया था ।

**आरसीटी, गुवाहाटी में दूसरी न्यायपीठ के सृजन से एक सदस्य (न्यायिक) का पद रिक्त है । दूसरा पद 22.04.2020 को रिक्त हो गया था । श्री लाभ सिंह, सदस्य (न्यायिक) ने तारीख 11.10.2021 को आरसीटी, गुवाहाटी में अपना पद ग्रहण किया था और उसके पश्चात् उन्हें आरसीटी, इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था ।

*** भोपाल में तारीख 05.11.2018 से एक सदस्य (न्यायिक) का पद रिक्त था । श्री विजयंत सिहं, सदस्य (न्यायिक) ने आरसीटी, भोपाल में तारीख 24.06.2021 को अपना पद ग्रहण किया था और उसके पश्चात् उन्हें आरसीटी, अहमदाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था।

**** आरसीटी, जयपुर में तारीख 07.10.2018 से सदस्य (न्यायिक) का पद रिक्त था । श्री उमेश कुमार शर्मा सदस्य (न्यायिक) ने आरसीटी, जयपुर में तारीख 09.07.2021 को अपना पद ग्रहण किया था और उसके पश्चात् उन्हें आरसीटी, पटना में स्थानांतरित कर दिया गया था ।

ग. **रेल दावा अधिकरण (आरसीटी) में रिक्तियों को नहीं भरे जाने के कारण :-**

दिसंबर, 2020 तक उद्भूत होने वाली अध्यक्ष (न्यायिक साथ ही साथ तकनीकी) और सदस्य (न्यायिक साथ ही साथ तकनीकी) के विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों की सूचना मई, 2020 में जारी की गई थी । तथापि, मद्रास विधिज्ञ परिषद् ने अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हता, अनुभव और सेवाओं की अन्य शर्तें) नियम, 2020 के उपबंधों को पुन: चुनौती दी थी । माननीय उच्चतम न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य (2020) एससी ऑनलाइन 962 {डब्ल्यू पी (सी)सं. 804/2020} के मामले में अपने तारीख 27 नवंबर, 2020 के निर्णय में पात्रता मानदंड और सेवा की शर्तों जिनके कारण उपाध्यक्ष और सदस्य के विभिन्न पदों के लिए जारी रिक्तियों की सूचनाएं निष्फल हो गई थीं, में कतिपय उपांतरणों के साथ 2020 के नियमों को विधिमान्य निर्णीत किया था ।

2021 के अध्यादेश के स्थान पर अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 तारीख 13/08/2021 को प्रभावी हुआ था । उसके आधार पर अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 पात्रता मानदंड और सेवा की शर्तों का विवरण देते हुए तारीख 15/09/2021 को अधिसूचित किए गए थे ।

इसको ध्यान में रखते हुए, तारीख 18/09/2021 को उपाध्यक्ष (न्यायिक) और उपाध्यक्ष (तकनीकी) प्रत्येक के दो पद, न्यायिक सदस्य के 16 पदों और तकनीकी सदस्य के 07 पदों के लिए रिक्तियों की सूचनाएं जारी की गई थीं । इन रिक्तियों के लिए चयन का संचालन करने के लिए खोज-सह-चयन समिति का भी गठन किया गया है ।

उपाबंध-6

राजस्व विभाग {केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी) और अपील अधिकरण (एसएएफईएमए) }:

क. जी हां

ख. अध्यक्ष/सदस्यों की रिक्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

सीईएसटीएटी			
क्र.सं.	**न्यायपीठ का नाम**	**सदस्यों के रिक्त पद**	**वह तारीख जिससे पद रिक्त हैं**
1	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली	4	एम(जे)-29.09.2017 एम(टी)-07.07.2015 एम(टी)-10.01.2020 एम(टी -28.11.2020
2	सीईएसटीएटी, मुम्बई	2	एम(जे)-15.12.2017 एम(जे)-07.05.2021
3	सीईएसटीएटी, कोलकाता	1	एम(टी) -13.05.2019
4	सीईएसटीएटी, चैन्नई	2	एम(टी) -02.05.2019 एम(जे)-01.03.2016
5	सीईएसटीएटी, बैंगलौर	4	एम(जे)-26.08.2021
6	सीईएसटीएटी, अहमदाबाद	1	एम(टी) -17.07.2015
7	सीईएसटीएटी, चंडीगढ़	1	एम(टी) -01.10.2019
8	सीईएसटीएटी, इलाहाबाद	2	एम(टी) -17.08.2020 एम(जे)-19.12.2020
	कुल	17	

अपील अधिकरण (एसएएफईएमए)			
क्र.सं.	**पदों का नाम**	**रिक्त पद**	**वह तारीख जिससे पद रिक्त हैं**
1	अध्यक्ष	1	22.09.2019
2	सदस्य	4	01.09.2017 28.05.2018 26.08.2019 03.04.2021
	कुल	5	

ग. अध्यक्ष और सदस्यों की निबंधनों और सेवा शर्तों को शासित करने वाले नियमों को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । वर्तमान में, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की अधिनियमिती और नए अधिकरण नियमों की अधिसूचना के परिणामस्वरूप अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है ।

उपाबंध-7

वित्तीय सेवाएं विभाग {ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपील अधिकरण}:

(क) और (ख) : वर्तमान में, अध्यक्ष के पांच स्वीकृत पद में से सभी पांच पद भरे हुए हैं । इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारियों के 39 स्वीकृत पदों में से 26 पद भरे हुए हैं और शेष 13 पद रिक्त हैं । तथापि, सभी 13 रिक्त पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का प्रस्ताव पहले ही जारी किया जा चुका है । 39 डीआरटी में पीठासीन अधिकारियों और 5 डीआरएटी में अध्यक्षों के पदधारण की स्थिति निम्नानुसार है:

39 डीआरटी में पीठासीन अधिकारियों और 5 डीआरएटी में अध्यक्षों के पदधारण की स्थिति		
क्र.सं.	**डीआरटी का नाम**	**पीठासीन अधिकारी**
1	डीआरटी -1, अहमदाबाद	10.08.2021 से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
2	डीआरटी -2, अहमदाबाद	भरा हुआ है
3	डीआरटी इलाहाबाद	भरा हुआ है
4	डीआरटी औरंगाबाद	भरा हुआ है
5	डीआरटी -1,बैंगलुरु	भरा हुआ है
6	डीआरटी -2,बैंगलुरु	भरा हुआ है
7	डीआरटी -I, चंडीगढ़	भरा हुआ है
8	डीआरटी -2, चंडीगढ़	भरा हुआ है
9	डीआरटी -3, चंडीगढ़	*23.02.2021* से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
10	डीआरटी -1, चैन्नई	*24.02.2021* से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
11	डीआरटी -2, चैन्नई	भरा हुआ है
12	डीआरटी -3, चैन्नई	भरा हुआ है
13	डीआरटी कोयंबटूर	भरा हुआ है
14	डीआरटी, कटक	भरा हुआ है
15	डीआरटी -1, दिल्ली	*07.01.2020* से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
16	डीआरटी -2, दिल्ली	*03.03.2021* से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
17	डीआरटी -3, दिल्ली	*01.01.2021* से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
18	डीआरटी, देहरादून	*19.02.2021* से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
19	डीआरटी -1, एर्नाकुलम	भरा हुआ है
20	डीआरटी -2, एर्नाकुलम	भरा हुआ है
21	डीआरटी, गुवाहाटी	भरा हुआ है
22	डीआरटी -1, हैदराबाद	भरा हुआ है
23	डीआरटी -2, हैदराबाद	*20.10.2021* से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
24	डीआरटी, जबलपुर	भरा हुआ है
25	डीआरटी जयपुर	भरा हुआ है
26	डीआरटी -1, कोलकाता	*12.12.2020* से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
27	डीआरटी -2, कोलकाता	भरा हुआ है

28	डीआरटी -3, कोलकाता	भरा हुआ है
29	डीआरटी लखनऊ	भरा हुआ है
30	डीआरटी, मदुरै	*20.10.2021* से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
31	डीआरटी -1, मुम्बई	भरा हुआ है
32	डीआरटी -2, मुम्बई	भरा हुआ है
33	डीआरटी -3, मुम्बई	भरा हुआ है
34	डीआरटी, नागपुर	*13.02.2020* से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
35	डीआरटी, पटना	*06.01.2020* से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
36	डीआरटी पुणे	भरा हुआ है
37	डीआरटी, रांची	भरा हुआ है
38	डीआरटी, सिलिगुड़ी	*30.10.2021* से रिक्त- प्रस्ताव जारी किया गया है
39	डीआरटी विशाखापटनम	भरा हुआ है
	डीआरएटी का नाम	अध्यक्ष
1	इलाहाबाद डीआरएटी	भरा हुआ है
2	चैन्नई डीआरएटी	भरा हुआ है
3	दिल्ली डीआरएटी	भरा हुआ है
4	कोलकाता डीआरएटी	भरा हुआ है
5	मुम्बई डीआरएटी	भरा हुआ है

उपाबंध-8

रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय (सशस्त्र बल अधिकरण) :

(**क) और (ख):** एएफटी में सदस्यों के स्वीकृत 34 पदों (अध्यक्ष और 17 प्रशासनिक सदस्यों सहित 17 न्यायिक सदस्य) में से 22 पद (10 न्यायिक सदस्य और 12 प्रशासनिक सदस्य) रिक्त हैं । दो न्यायिक सदस्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित तारीख 09.12.2019 के अंतरिम आदेश के आधार पर कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारीवृंद की स्वीकृत पद सं. 559 में से 248 पद रिक्त हैं । **तारीख** 22.03.2022 **को सशस्त्र बल अधिकरण में न्यायिक सदस्यों की रिक्तियों की स्थिति**

पद	रिक्ति की तारीख
न्यायिक सदस्य	12.11.2018
न्यायिक सदस्य	20.01.2018
न्यायिक सदस्य	16.08.2019
न्यायिक सदस्य	07.07.2016
न्यायिक सदस्य	18.08.2019
न्यायिक सदस्य	09.06.2018
न्यायिक सदस्य	30.07.2016
न्यायिक सदस्य	20.05.2019
न्यायिक सदस्य	22.03.2018
न्यायिक सदस्य	17.10.2017
न्यायिक सदस्य *	-
न्यायिक सदस्य*	-

* न्यायिक सदस्य, माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद ताहिर (सेवानिवृत्त) और माननीय न्यायमूर्ति सुश्री सुनीता गुप्ता (सेवानिवृत्त) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 09.12.2019 के अंतरिम आदेश के आधार पर पद धारण कर रहे हैं

<u>तारीख 22.03.2022 को सशस्त्र बल अधिकरण में प्रशासनिक सदस्यों की रिक्तियों की स्थिति</u>

पद	रिक्ति की तारीख
प्रशासनिक सदस्य	01.01.2021
प्रशासनिक सदस्य	01.09.2021
प्रशासनिक सदस्य	03.02.2018
प्रशासनिक सदस्य	20.11.2019
प्रशासनिक सदस्य	23.03.2018
प्रशासनिक सदस्य	23.08.2019
प्रशासनिक सदस्य	18.05.2019
प्रशासनिक सदस्य	30.12.2017
प्रशासनिक सदस्य	09.01.2021
प्रशासनिक सदस्य	26.06.2019
प्रशासनिक सदस्य	19.01.2019
प्रशासनिक सदस्य	14.02.2022

(ग) : मंत्रालय, एएफटी में सदस्यों की नियुक्ति के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है । हाल ही में, सितंबर, 2021 में, तीन नए न्यायिक सदस्यों ने एएफटी में कार्यभार ग्रहण किया है । जहां तक कि एएफटी के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति का संबंध है विद्यमान आरआर के अनुसार रिक्तियों को विज्ञापित किया जा चुका है । उन्हें भरने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है ।

उपाबंध-9

दूरसंचार विभाग { दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी)}:

(क) से (ग) : टीआरएआई अधिनियम की धारा 14ख के अनुसार टीडीएसएटी एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर बना होता है । एक अध्यक्ष और एक सदस्य का पद पहले से ही भरा हुआ है । सदस्य का एक पद 19.10.2019 से रिक्त है । उक्त पद के लिए खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाना है ।

****